शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 48 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 48 अंक – 10 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 6 – 13 मार्च 2023 मूल्य पांच रूपए

ग्लोबल इन्वैस्टर मीट में हस्ताक्षरित 96720 करोड़ के निवेश और 1,96,800 रोजगारों का क्या हुआ

- उद्योग विभाग के 250 एमओयू में आना था 17063.22 करोड़
- पर्यटन में 16559.94 करोड़ के 225 एमओयू हुये थे साइन
- आवास में आना था 12054.50 करोड़ का निवेश
- इस असफलता के लिये कौन है जिम्मेदार राजनीतिक नेतृत्व या प्रशासन

शिमला/शैल। कांग्रेस ने जो दस गारंटीयां प्रदेश की जनता को चुनाव से पहले दी हैं उनमें से एक पांच लाख रोजगार उपलब्ध करवाने की भी है। सभी गारंटीयों को कैसे पूरा किया जायेगा इसके लिये रोडमैप तैयार करने का काम कुछ कमेटीयों को सौंपा गया है। पांच लाख रोजगार सरकार में ही सृजित नहीं किये जा सकते क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या ही तीन लाख से कम है। स्वभाविक है कि इतना रोजगार पैदा करने के लिये प्राईवेट सैक्टर का भी सहारा लेना पड़ेगा। प्राइवेट सैक्टर के निवेश की व्यवहारिक स्थिति क्या है इसकी जानकारी जयराम सरकार के समय में वर्ष 2019 में आयोजित ग्लोबल इन्वैस्टर मीट से जुटाई जा सकती है। धर्मशाला में आयोजित हुई इस मीट में निवेशकों को बुलाने के लिये देश और विदेश में रोड शो आयोजित किये गये थे। इन आयोजनों पर करीब 12 करोड़ रुपये खर्च हो गये हैं। लेकिन इतने बड़े आयोजन के बाद इस मीट का व्यवहारिक परिणाम क्या निकला है। स्मरणीय है कि इस मीट में 96720 करोड़ के प्रस्तावित निवेश के 703 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुए थे और इस निवेश से 1,96,800 लोगों को रोजगार हासिल होने का दावा किया था। सरकार के 19 विभागों ने यह समझौता ज्ञापन साईन किये थे। यदि करीब एक लाख करोड़ के निवेश से करीब दो लाख रोजगार पैदा होने का अनुमान था तो पांच लाख रोजगार के लिए करीब चार लाख करोड़ का निवेश होना चाहिये।

इस निवेश मेले में सबसे अधिक 250 ज्ञापन उद्योग विभाग ने साइन किये थे और इसमें 17063.22 करोड़ का निवेश होना था। दूसरे स्थान पर पर्यटन था और इसमें 16559.94 करोड़ के 225 ज्ञापन हस्ताक्षरित हुये थे। आयुष विभाग में 1269.25 करोड़ के निवेश के 45 ज्ञापन और उच्च शिक्षा में 1713 करोड़ के 44 एमओयू साईन हुए थे। हाउसिंग के 33 एमओयू में 12054.50 करोड़ निवेश होना था। इस मीट में जितना निवेश आने के एमओयू साईन हुये थे और रोजगार का दावा किया गया यदि इन दावों का आधा भी व्यवहार में होता तो प्रदेश पर शायद इतना कर्ज भी न होता और बेरोजगारी में देश के पहले छः राज्यों में प्रदेश न आता। आज भी सरकार पर्यटन के क्षेत्र में ए.डी.बी का 1311 करोड़ का कर्ज निवेश करने जा रही है। 2019 की ग्लोबल इन्वैस्टर मीट से पहले भी ए.डी.बी. का 256.99 करोड़ कर्ज निवेशित हो चुका है। लेकिन इस सबके बाद भी परिणाम यह है कि 28-9-2019 को हस्ताक्षरित हुए 225 एम ओ यू में से शायद एक भी जमीन पर नही उतर पाया है।

रोजगार गारंटी के परिप्रेक्ष में उठी चर्चा

एमओ यू को अमलीजामा पहनाने के लिये तीन बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं। पहली जमीन दूसरी कैपिटल और तीसरी मार्केटिंग। यदि इनमें से एक की भी कमी हो तो कोई भी परियोजना सिरे नहीं चढ़ती है। इसलिये जिस इन्वैस्टर मीट पर प्रदेश के आम आदमी का करोड़ों रुपया आयोजन पर निवेश कर दिया गया है उसके वांछित परिणाम क्यों सामने नहीं आये हैं यह कारण जानने का आम आदमी को अधिकार है। यह सामने आना चाहिये कि क्या सरकार इन लोगों को जमीन ही उपलब्ध करवा पायी। या इनके पास वांछित कैपिटल का अभाव था या निवेश के बाद मार्केटिंग की सुविधायें नहीं थी। जिन विभागों ने यह एमओयू साइन किये थे उन्होंने इन्हें अमलीजामा पहनाने के लिये क्या कदम उठाये? क्या निवेशकों से कोई पत्राचार किया गया तो उसका क्या परिणाम सामने आया। यह सब प्रदेश के आम आदमी के सामने रखा जाना चाहिये। क्योंकि इस सरकार को भी वायदा किये रोजगार पैदा करने के लिए प्राइवेट सैक्टर का ही सहारा लेना पड़ेगा। पिछली सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग के तहत दो रोजगार योजनाएं घोषित की थी। अब इस सरकार ने उन दोनों योजनाओं को एक करके उद्योग विभाग को जिम्मेदारी दे दी है। लेकिन उन योजनाओं के तहत कितने लोगों को रोजगार मिल पाया है इसका कोई आंकड़ा सामने नहीं आ पाया है। यदि डबल इंजिन की सरकार के समय में भी निवेशक प्रदेश में नहीं आ पाया है तो आज कैसे आ पायेगा यह बड़ा सवाल है। जबकि प्रधानमंत्री और केन्द्रिय वित्त मन्त्री हर आदमी को कर्ज के लिये प्रेरित कर रहे थे। बैंकों को खुले मन से कर्ज बांटने के निर्देश थे। इस सबके बावजूद प्रदेश में यह प्रस्तावित निवेश क्यों नहीं आ पाया इसके कारण सामने आने ही चाहिये।

यह था प्रस्तावित निवेश

	विभाग	एमओयू	निवेश
1.	कृषि	2	225 करोड़
2.	आयुष	45	1269.25 करोड़
3.	प्रारंभिक शिक्षा	5	6.85 करोड़
4.	उच्च शिक्षा	44	1713 करोड़
5.	मत्स्य पालन	1	7 करोड़
6.	वन	1	25 करोड़
7.	स्वास्थ्य	5	632 करोड़
8.	बागवानी	6	77.55 करोड़
9.	उद्योग	250	17063.22 करोड़
10.	आईटी	14	2833.21 करोड़
11.	भाषा कला संस्कृति	1	25करोड़
12.	उर्जा	18	34112 करोड़
13.	कौशल विकास	7	15 करोड़
14.	खेल	2	116 करोड़
15.	तकनीकी शिक्षा	1	300 करोड़
16.	पर्यटन	225	16559.94 करोड़
17.	परिवहन	13	3658 करोड़
18.	शहरी विकास	30	6027.66 करोड़
19.	आवास	33	12054.50 करोड़

राज्यपाल ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण पर बल दिया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने ऐतिहासिक गेयटी थियेटर में 12 मार्च से 18 मार्च, 2023 तक नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा आयोजित किए जा रहे 14वें जनजातीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के अवसर पर सम्बोधित करते हुए कहा कि इस तरह के संवाद व आदान-प्रदान कार्यक्रमों के माध्यम से

देश की सामाजिक-सांस्कृतिक विरासत, परम्पराओं एवं अर्थव्यवस्था की झलक देखने को मिलती है। उन्होंने जनजातीय समाज को आत्मनिर्भर बनने के साथ-साथ भारत निर्माण के लिए अपने कर्तव्य का पूर्ण समर्पण के साथ निर्वहन करने का आह्वान किया।

नेहरू युवा केंद्र संगठन, हिमाचल प्रदेश द्वारा आयोजित किये जा रहे इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न जिलों, विशेषकर छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्यप्रदेश तथा उड़ीसा के लगभग 200 जनजातीय युवा भाग ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस तथा सशस्त्र सीमा बल के 20 जवान ने भी कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं।

राज्यपाल ने इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सभ्यता को प्रदर्शित करने वाले युवाओं के संयुक्त प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से पिछले 75 वर्षो में भारत में हुए विकास के प्रति व्यापक जागरूकता की परिकल्पना की गई है। यह कार्यक्रम जनजातीय युवाओं को विविधता में एकता की अवधारणा को अपनाने और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि देश के अगले 25 वर्ष की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है जिसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'अमृत काल' कहा है। उन्होंने कहा कि इस अमृतकाल के पांच संकल्पों में विकसित भारत, गुलामी की प्रत्येक सोच से स्वतंत्रता, विरासत पर गौरव, एकता तथा आपसी प्रेम और नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्य निभाना शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को इन संकल्पों के कार्यान्वयन में अपना बहुमूल्य योगदान देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि इस अमृतकाल के दौरान हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों की आशाओं को पूर्ण करने के लिए हमें तीव्र गति से कार्य करने की आवश्यकता है तथा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी के प्रयास तथा सभी के कर्तव्य की भावना के साथ आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय क्षेत्रों के लोगों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है।

कार्यक्रम के सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए राज्यपाल ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से जनजातीय समाज की समृद्ध संस्कृति, परम्पराओं तथा रीति-रिवाजों का आदान-प्रदान सुनिश्चित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के जनजातीय युवाओं को अन्य जनजातीय जिलों का भ्रमण भी करना चाहिए ताकि एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार हो सके।

इस अवसर पर राज्यपाल ने सचिव राजेश शर्मा, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के उप-महानिरीक्षक प्रेम सिंह तथा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के विधि विभाग के अधिष्ठाता संजय सिंधु को सम्मानित भी किया।

इसके उपरान्त, राज्यपाल ने जनजातीय युवा यात्रा को हरी झंडी दिखाई।

नेहरू युवा केन्द्र संगठन के राज्य निदेशक सैमसन मसीह ने राज्यपाल का स्वागत किया तथा संगठन की विभिन्न गतिविधियों से उन्हें अवगत करवाया।

जिला युवा अधिकारी, मनीषा अधिकारी ने इस अवसर पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

राज्यपाल ने नौणी विश्वविद्यालय में आवश्यक सुविधाओं में सुधार के निर्देश दिए

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में पीलिया सम्बन्धी मामले का संज्ञान लेते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. राजेश्वर चंदेल को इस संदर्भ में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

राज्यपाल ने कुलपति को विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने और अन्य सुविधाओं में सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस मामले की विस्तृत जांच कर वास्तविक स्थिति के बारे में अवगत के निर्देश भी दिए।

राज्यपाल ने विद्यार्थियों से परिसर में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने का आहवान किया। उन्होंने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से इस मामले की निगरानी करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

राज्यपाल ने होली पर्व पर लोगों को बधाई दी

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने होली पर्व के अवसर पर

प्रदेशवासियों को बधाई दी है।

शुक्ल ने कहा कि रंगों के त्योहार होली का अपना विशेष महत्व और विशिष्ट पहचान है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह त्योहार भाईचारे की भावना को और मजबूत करेगा और देश की एकता एवं अखंडता को बढ़ावा देगा।

होली पर्व की पूर्व संध्या पर राज्यपाल एवं लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल ने राजभवन के कर्मचारियों के साथ रंगों का त्योहार मनाया। उन्होंने राजभवन परिवार के सभी सदस्यों को होली की बधाई देते हुए मिठाइयां भी भेंट कीं।

प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत

शिमला/शैल। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में केवल 60 से कम विद्यार्थियों की संख्या वाले महाविद्यालयों को डिनोटीफाई किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार द्वारा नए शैक्षणिक संस्थानों को क्रियाशील करने के लिए पर्याप्त स्टाफ, भूमि के स्वामित्व के हस्तांतरण तथा नए भवनों के निर्माण के लिए धन उपलब्ध करवाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त इन संस्थानों में आवश्यक बुनियादी अधोसंरचना सृजित करने के लिए भी कोई प्रयास नहीं किये गये। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कई संस्थान अपर्याप्त कर्मचारियों के साथ क्रियाशील हैं और कुछ कक्षाएं केवल नाममात्र कर्मचारियों और एक अध्यापक की तैनाती कर चलाई जा रही है। पूर्व भाजपा सरकार ने सिर्फ संस्थानों की संख्या बढ़ाने के दृष्टिगत लगातार घोषणायें कीं। इन संस्थानों में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है इसी के दृष्टिगत विभिन्न निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा विद्यार्थियों का भविष्य उज्ज्वल बनाने एवं उनके लिए रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में दृढ़ प्रयास किए जा रहे हैं। रोहित ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार छात्रों के भविष्य की आवश्यकताओं और प्रतिस्पर्धा के दौर में ध्येय को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के उद्देश्य से भी अनेक महत्वाकांक्षी कदम उठा रही है। विभिन्न संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और नवीनतम प्रौद्योगिकी आधारित पाठयक्रम आरंभ करने की योजना तैयार की जा रही है ताकि छात्रों को वैश्विक स्तर पर रोज़गार के अवसर उपलब्ध हो सकें।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सभी बच्चों के लिए समावेशी, समान तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों तथा शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए सभी उचित कदम उठाए गए हैं।

उन्होंने कहा कि पिछली सरकार अपने कार्यकाल के अंतिम छह महीनों में बजटीय प्रावधानों के बिना 920 संस्थान खोले और स्तरोन्नत किए गए। जो विद्यार्थियों और राज्य की भलाई के बजाय राजनीतिक हितों से प्रेरित थे।

मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को होली उत्सव की शुभकामनाएं दीं

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने होली पर्व के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि होली का त्यौहार आपसी प्रेम एवं सौहार्द का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि होली के रंग हमारी बहुविध-सांस्कृतिक विरासत को सहेजते हुए विविधता में एकता का संदेश देते हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह त्यौहार प्रदेश और यहां के लोगों के जीवन में सुख-समृद्धि और खुशियां लेकर आएगा।

उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने होली के त्यौहार पर अपने संदेश में कहा कि इस पर्व का सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व है। यह पर्व हमें आपस में मेल-जोल से रहने तथा एक-दूसरे के साथ अपनी खुशियां साझा करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने राज्य के लोगों को इस अवसर पर बधाई देते हुए उनकी सुख-समृद्धि की कामना की है।

नौणी विवि के वैज्ञानिक ब्रिटेन के विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर नियुक्त

शिमला/शैल। डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी के प्लांट पैथोलॉजी विभाग में प्रोफेसर डॉ. अनिल हांडा को यूनाइटेड किंगडम के यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक के स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज में विजिटिंग प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया है। डॉ. हांडा वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम में तीन सप्ताह के अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पर गए हैं। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम विश्वविद्यालय में चल रहे आईसीएआर एनएएचईपी की संस्थागत विकास योजना द्वारा प्रायोजित किया गया है। मेजबान संस्थान में विजिटिंग प्रोफेसरशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम की पूरी अवधि के लिए है। उनके साथ विश्वविद्यालय के एक अन्य वैज्ञानिक डॉ. बंटी शायला भी यूनाइटेड किंगडम गयी हुई है।

डॉ. हांडा ने इस सप्ताह वारविक विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर वेलस्बॉर्न में एक व्याख्यान दिया, जिसमें वारविक विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी के संकाय और छात्रों ने भाग लिया। उन्होंने शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार गतिविधियों के संदर्भ में नौणी विवि के कार्य के बारे में बताया। उन्होंने विश्वविद्यालय में प्लांट पैथोलॉजी विभाग की गतिविधियों और प्लांट वायरोलॉजी में अपने शोध को भी प्रस्तुत किया। यह व्याख्यान वारविक के सभी परिसरों और यूके के कुछ अन्य विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन दिखाया गया। उनके शोध कार्य की विश्वविद्यालय के छात्रों और फैकल्टी ने सराहना की।

आईडीपी के प्रधान अन्वेषक डॉ. केके रैना ने बताया कि नौणी विवि के 24 वैज्ञानिक वर्तमान में 15 दिनों से लेकर 3 महीने तक के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, थाईलैंड और इजराइल जैसे देश गये हैं। आने वाले हफ्तों में तीन और वैज्ञानिक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए रवाना होंगे। नौणी विवि के कुलपति प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल ने डॉ. हांडा को उनकी उपलब्धि और विश्वविद्यालय के कार्य को एक अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठित संस्थान में बढ़ावा देने के लिए बधाई दी। यूनिवसिटी फैकल्टी, स्टाफ और छात्रों ने भी डॉ. हांडा को बधाई दी।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादकः जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकारः ऋचा

नियमों का उल्लंघन करने पर 1180 वाहनों के चालान कर वसूला 28,46,650 जुर्माना

शिमला/शैल। परिवहन विभाग के प्रवक्ता ने बताया विगत दस दिनों में मोटर वाहन अधिनियम व नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के 1180 चालान कर 28,46,650 रूपए की राशि बतौर जुर्माना वसूल की गयी है।

उन्होंने बताया कि वाहनों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कुछ निजी वाहन मालिक अपने वाहनों का उपयोग गैर कानूनी तरीके से व्यवसायिक वाहनों के रूप में कर रहे हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों पर विभागीय अधिकारियों द्वारा मोटर वाहन अधिनियम व नियमों के अंतर्गत जुर्माना लगाया गया। उन्होंने वाहन संचालकों को बताया कि भविष्य में निजी वाहनों का व्यवसायिक प्रयोग करने वालों के वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा भविष्य में भी पूरे प्रदेश में वाहन निरीक्षण अभियान जारी रखा जाएगा।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने विशेष बच्चों के साथ होली मनायी

शिमला/शैल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने विशेष रूप से योग्यता वाले बच्चों के संस्थान ढली तथा नारी सेवा सदन मशोबरा में होली उत्सव मनाया।

इस अवसर पर डॉ. शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया है। इन बच्चों की देखभाल और बेहतर शिक्षा प्रदान करना प्रदेश सरकार का दायित्व है। इस दिशा में सरकार ने अनेक महत्वाकांक्षी कदम उठाये है।

मुख्यमंत्री ने शोंगटोंग जलविद्युत परियोजना को जुलाई 2025 तक पूरा करने के निर्देश दिए

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपरेशन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने 450 मैगावॉट क्षमता की शोंगटोंग जलविद्युत परियोजना को

जुलाई, 2025 तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के लिए वर्ष 2012 में निविदा जारी की गयी थी लेकिन विभिन्न कारणों से इसके निर्माण कार्य में विलंब हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं में विलंब के कारण इनकी निर्माण लागत में वृद्धि होती है जिससे राज्य को नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि सभी परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश पॉवर कॉरपरेशन लिमिटेड (एचपीपीसीएल) के अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर सभी बाधाओं का निराकरण कर तीन माह के पश्चात एक और समीक्षा बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने परियोजना के निर्माण के लिए उत्तरादायी कंपनी को श्रम शक्ति में वृद्धि कर शेष निर्माण कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के लिए कहा।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शोंगटोंग जल विद्युत ऊर्जा परियोजना के पूरा होने से वार्षिक 1579 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन होगा। इससे राज्य में 1300 करोड़ रुपये का विद्युत उत्पादन होगा। परियोजना के समयबद्ध कार्यान्वित होने से 250 करोड़ रुपये की बचत होगी जिससे राजस्व पर 156 करोड़ रुपये की ब्याज़ उपलब्ध होगी, जिससे प्रदेश को कुल 1706 करोड़ रुपये का लाभ होगा।

मुख्यमंत्री ने लाभ अर्जित करने वाली तथा राजस्व उत्पन्न करने वाली परियोजनाओं की क्षमता बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाएगा। उन्होंने इस परियोजना को समयबद्ध पूरा करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कार्य करने पर बल दिया। राज्य सरकार जल विद्युत और सौर ऊर्जा के उपयोग से हिमाचल को वर्ष 2025 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त राज्य ने वर्ष 2024 के अन्त तक 500 मेगावॉट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है।

इस अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव अभिषेक जैन, बहुउद्देशीय ऊर्जा परियोजना एवं ऊर्जा सचिव राजीव कुमार, एचपीपीसीएल के प्रबंध निदेशक हरिकेश मीणा, निदेशक डॉ. अमित कुमार, अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा निर्माण कम्पनी के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

पहली से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को वर्दी के लिये मिलेंगे 600 रुपये:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। राज्य सरकार ने पहली से आठवीं कक्षा तक के सभी लड़कों व लड़कियों को निःशुल्क स्कूल वर्दी के लिए 600 रुपये प्रति विद्यार्थी प्रदान करने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश के लगभग 5.25 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। यह जानकारी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी।

उन्होंने कहा कि वर्दी की यह राशि विद्यार्थी अथवा उनकी माता के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से अंतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों के माता-पिता का आर्थिक बोझ कम करने के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से राशि सीधे लाभार्थी को भेजने से इसमें पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सदैव तत्पर है और उन्हें लाभान्वित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कृतसंकल्प है और इसके दृष्टिगत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चरणबद्ध ढंग से राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। इन मॉडर्न स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ ही विद्यार्थियों को उचित शैक्षणिक वातावरण और विभिन्न गतिविधियों के लिए पर्याप्त स्थान भी उपलब्ध करवाया जाएगा।

बागवानों के लिए परागण प्रबन्धन पर विशेष प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन

शिमला/शैल। निदेशक उद्यान संदीप कदम ने बताया कि उद्यान विभाग द्वारा प्रदेश में सेब की अच्छी पैदावार के दृष्टिगत 10 मार्च से 22 मार्च, 2023 तक सेब के बागीचों में परागण प्रबन्धन विषय पर विशेष जागरूकता एवं प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन विशेष शिविरों में लगभग 8 हजार बागवानों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

इस अभियान के लिए विभाग के 60 अधिकारियों को प्रशिक्षित कर मास्टर ट्रेनर नियुक्त किया गया है।

अभियान के अंतर्गत प्रदेश के सेब उत्पादन वाले क्षेत्रों में हर विकास खंड में 200 किसानों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसमें मधुमक्खियों द्वारा परागण के महत्व, फल पैदावार बढ़ोत्तरी के लिए मधुमक्खियों की कॉलोनियों की देखभाल सहित विभिन्न विषयों के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने एकदिवसीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के इच्छुक बागवानों को अपने नजदीकी उद्यान विकास अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क करने का आहवान किया।

परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग पर अंकुश लगाने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही प्रदेश सरकार: रोहित ठाकुर

शिमला/शैल। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि प्रदेश सरकार ने परीक्षाओं में शुचिता बनाए रखने तथा अनुचित साधनों के प्रयोग पर अंकुश लगाने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। इसके पीछे सरकार का ध्येय ईमानदार व परिश्रमी छात्रों को प्रोत्साहित करना है।

रोहित ठाकुर ने बताया कि सभी निजी और सरकारी संस्थानों को परीक्षाओं के दौरान कड़ी निगरानी रखने के लिए उचित कदम उठाने तथा दोषियों के विरूद्ध सख्त कारवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में कदाचार एक गंभीर चिंता का विषय है तथा इससे परीक्षा आयोजित करने का संपूर्ण उद्देश्य ही निष्फल हो जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्वतंत्र और निष्पक्ष परीक्षाएं सुनिश्चित करने तथा कदाचार को रोकने के लिए सभी एहतियाती उपाय कर रही है। परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग पर रोक लगाने के लिए विश्वविद्यालय एवं शिक्षण संस्थानों के स्तर पर एक विशेष उच्च स्तरीय समिति गठित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। यह समिति परीक्षाओं में किसी भी प्रकार के कदाचार पर अंकुश लगाने के लिए उत्तरदायी होगी।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों एवं अन्य संस्थानों को परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए है। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान नकल करते और करवाते हुए पकड़े जाने पर सख्त से सख्त कारवाई की जाएगी। निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करवाने के दृष्टिगत उड़नदस्तों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। यह उड़न दस्ते परीक्षाओं के दौरान औचक निरीक्षण करेंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भी निगरानी रखने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को गंभीरता से ले रही है और इसमें किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री सुख-आश्रय कोष में ऑनलाइन अंशदान की सुविधा

शिमला/शैल। सुख-आश्रय कोष में अब ऑनलाइन माध्यम से भी अंशदान किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में मुख्यमंत्री सुख-आश्रय कोष के लिए ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया।

अंशदाता https://sukhashray-hp.nic.in. पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अंशदान कर सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से अंशदाता ऑनलाइन भुगतान की रसीद भी डाउनलोड कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पोर्टल में अंशदाताओं की सूची और अब तक ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कुल धनराशि की जानकारी उपलब्ध है। इस पोर्टल में धनराशि के वितरण के संबंध में भी जानकारी उपलब्ध होगी। इस पहल से प्रणाली में और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना अनाथ बच्चों और निराश्रित महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गयी है। उन्होंने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि विभिन्न संस्थाएं और व्यक्ति सुख-आश्रय कोष में अंशदान देने के लिए आगे आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने स्वयं इस कोष के लिए एक माह का वेतन और कांग्रेस विधायकों ने भी एक-एक लाख रुपये का अंशदान किया है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने समाजसेवियों, आम जनता और समाज के सुविधा संपन्न वर्गों से इस कोष के लिए उदारतापूर्वक योगदान करने का आग्रह किया ताकि इसके माध्यम से अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान की जा सके।

जल विद्युत परियोजनाओं पर वाटर सेस से राज्य के आम जन पर नहीं पड़ेगा कोई प्रभाव

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार आर्थिक संसाधनों में वृद्धि के लिए विभिन्न कदम उठा रही है। हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाओं पर लगाया गया जल उपकर (वाटर सेस) इन्हीं में से एक है।

उन्होंने बताया कि इस उपकर के दायरे में प्रदेश की 172 जल विद्युत परियोजनाओं को लाया गया है। उन्होंने कहा कि केवल इन्हीं चिन्हित जल विद्युत परियोजनाओं से ही राज्य सरकार जल उपकर वसूल करेगी और राज्य के आम जन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ही नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्य उत्तराखंड तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में भी जल विद्युत परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाया गया है।

प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने राजस्व में वृद्धि करने की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं और वाटर सेस लागू करना भी ऐसा ही एक उपाय है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश के आर्थिक संसाधनों में वृद्धि और राज्य की अर्थव्यस्था को संबल प्रदान कर राजस्व में बढ़ोतरी करना है, ताकि जन कल्याणकारी नीतियों के लिए सरकार के पास पर्याप्त धन उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल विद्युत परियोजनाओं से वाटर सेस की राशि परियोजना के आकार सहित विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर वसूल करेगी।

प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 10 मार्च, 2023 से हिमाचल प्रदेश वॉटर सेस ऑन हाईड्रोपावर जनरेशन अध्यादेश लागू कर दिया गया है तथा आगामी विधानसभा सत्र में हिमाचल प्रदेश वॉटर सेस ऑन हाईड्रोपावर जनरेशन विधेयक 2023 भी लाया जाएगा, जिसके लिए प्रदेश मंत्रिमंडल ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

केहर सिंह खाची को राज्य वन विकास निगम का उपाध्यक्ष बनाने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया

शिमला/शैल। ठियोग विधानसभा क्षेत्र के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और केहर सिंह खाची को हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम का उपाध्यक्ष बनाने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

प्रतिनिधिमंडल को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केहर सिंह खाची लगभग 25 वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं और अब उन्हें सरकार में भी उचित सम्मान दिया गया है। उन्होंने कहा कि ठियोग के विधायक कुलदीप सिंह राठौर और केहर सिंह खाची के साथ चर्चा कर इस विधानसभा क्षेत्र में विकास को गति प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि वे सत्ता में सुख भोगने के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आये हैं तथा लोगों के कल्याण के लिए वर्तमान सरकार अनेक प्रभावी कदम उठा रही है।

ठियोग के विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने केहर सिंह खाची को राज्य वन विकास निगम का उपाध्यक्ष बनाये जाने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि इससे कार्यकर्त्ताओं का मनोबल और ऊंचा होगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी एकजुट होकर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करेंगे।

राज्य वन विकास निगम के नवनियुक्त उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची ने कहा कि वे उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूर्ण प्रयास करेंगे और नये दायित्व का निर्वहन पूर्ण निष्ठा के साथ करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवाद की राजनीति को समाप्त करते हुए सभी क्षेत्रों को सरकार में उचित प्रतिनिधित्व दिया है।

योग्य सहायकों के बिना निर्णय करना बड़ा कठिन होता है।
..... चाणक्य

सम्पादकीय

क्या राहुल के ब्यानों पर भाजपा की प्रतिक्रियाएं मोदी सरकार का डर है

क्या कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ब्रिटेन में दिये बयानों से भारत का अपमान हुआ है? यह सवाल भाजपा और मोदी सरकार की प्रतिक्रियाओं के बाद एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिससे पिछले आठ वर्षों की सारी कार्यप्रणाली को जनता के आकलन के लिये लाकर खड़ा कर दिया है। वसुदेव कुटुम्बकम के ब्रह्म वाक्य पर आचरण करने का दावा करने वाले जब एक व्यक्ति के ब्यान से आक्रोशित हो उठे तो यह मानना पड़ेगा कि चोट बहुत गहरे तक लगी है। 2014 में जब अन्ना आन्दोलन ने सत्ता परिवर्तन की नीव रखी थी तब उस आन्दोलन का मुख्य मुद्दा था लोकपाल की स्थापना। 2G स्कैम के 1,76,000 करोड़ के आंकड़े ने पूरा देश हिला कर रख दिया था। लेकिन बाद में इस कैग रिपोर्ट के जनक विनोद राय ने अदालत में यह स्वीकार किया की 2G में कोई घपला हुआ ही नहीं है उन्हें गणना में गलती लगी है। क्या इससे देश की इज्जत बढ़ी थी? काले धन से हर भारतीय के खाते में पन्द्रह लाख आने का वायदा किया गया था जिसे बाद में जुमला कह कर टाल दिया गया। क्या इससे हर भारतीय का मान बढ़ा है? कोविड जैसी बीमारी को भगाने के लिये प्रधानमंत्री के निर्देश पर ताली थाली बजाई गयी। दीया जलाया गया क्या इससे देश का मान बढ़ा है? देश के अस्सी करोड़ लोग मुफ्त राशन पर जी रहे हैं क्या यह मान बढ़ाने वाली उपलब्धि है? क्या सरकार के इस दावे से ग्लोबल हंगर इन्डैक्स की भारत में भूख पर आयी रिपोर्ट मान बढ़ाने वाली बात है? विदेश की धरती पर जब देश का प्रधानमंत्री यह कहे कि देश में पिछले 70 वर्षों में कुछ नहीं हुआ है तो क्या उससे मान बढ़ा था। जब प्रधानमंत्री ने अमेरिका जाकर ट्रंप के लिये चुनाव प्रचार करते हुए यह कहा था कि ''अबकी बार ट्रंप सरकार तो क्या वह ट्रंप और अमेरिका को देश में दखल देने का न्योता नहीं था? आज जब भारतीय मूल के लोग विदेशों में कई मुल्कों की संसद और सरकार तक पहुंच गये हैं और देश के लोग उनकी इस उपलब्धि पर प्रसन्न होते हैं तो क्या वह लोग भारत की हर छोटी-बड़ी घटना पर नजर नहीं रख रहे हैं। क्या विदेशी मीडिया भारत में घटने वाली हर घटना को रिपोर्ट नही कर रहा है। राफेल सौदे पर उठे विवाद को लेकर भारत और फ्रांस के अलग स्टैंड पर विश्व में चर्चा नहीं हुई है। बीबीसी की डाक्यूमेंट्री क्या विदेशों में नहीं देखी गयी है? क्या बीबीसी के खिलाफ की गयी कारवाई विदेशों में रिपोर्ट नहीं हुई है? दी गार्जियन की रिपोर्ट क्या विदेशों में नही पढ़ी गयी है? क्या इसी रिपोर्ट के बाद चुनाव आयोग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला नहीं आया है। क्या हिन्डनबर्ग की रिपोर्ट ने विश्व के शेयर बाजार को प्रभावित नही किया है? राहुल गांधी के ब्यान पर उभरी प्रतिक्रिया ने पिछले आठ वर्षों की सारी छोटी-बड़ी घटनाओं को फिर से चर्चा में लाकर खड़ा कर दिया है। विश्व गुरु और विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के दावों को बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के आयने ने एकदम नंगा करके खड़ा कर दिया है। जो देश अपने प्रधानमंत्री को निर्देश पर आज के कम्प्यूटर युग में भी बिमारी को भगाने के लिये ताली थाली बजाये और दीया जलाये वह विश्व गुरु बनने के कितना करीब होगा इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है। ऐसे आचरण से हमारी वैद्धिकता क्या आंकी गयी होगी यह सोचकर भी डर लगता है। आज जिस तरह से केंद्रीय जांच एजैन्सियां विपक्ष के नेताओं के खिलाफ सक्रिय की गयी है उससे यह जन चर्चा चल पड़ी है कि सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष में ही हैं। भाजपा में जाकर सबके पाप धुल जाते हैं। भले ही हेमन्त विस्वा सरमा जैसे नेता जब कांग्रेस में थे तब उनके भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा ने पुस्तिका छाप दी थी और जांच की मांग की थी लेकिन भाजपा में जाते ही वह पाक साफ हो गये हैं। विपक्षी दलों से टूटकर जितने भी नेता भाजपा में गये हैं वह सब आरोप लगने के बाद ही गये हैं और भाजपा में जाकर अपराध मुक्त हो गये हैं। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जनता से जो वायदे किये गये थे अब 2024 के चुनाव में जनता उनका हिसाब न पूछे और विपक्ष का कोई नेता उन वायदों पर सवाल न उठाये इसलिये केंद्रीय जांच एजैन्सियों के सहारे विपक्ष और उसके महत्वपूर्ण नेताओं को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। आज कांग्रेस ही एक ऐसा राजनीतिक दल है जो देश के प्रत्येक गांव में जाना जाता है। कांग्रेस में राहुल गांधी का चरित्र हनन करने के लिये किस तरह के क्या क्या प्रयास किये गये हैं वह कोबरा पोस्ट के स्टिंग ऑपरेशन में सामने आ चुके हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जो चुनौती सरकार के सामने रखी है उससे सरकार हिल गयी है क्योंकि विदेशी मीडिया भी इस यात्रा को कवर कर रहा था। इस यात्रा में जो कुछ देश की जनता के सामने राहुल ने रखा है आज प्रवासी भारतीय उसी की पुष्टि के लिये उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं और यही मोदी सरकार को डर है।

बाज़ारवाद के इस दौर में क्या ग्राहक वाकई राजा है?

डॉ. नीलम महेंद्र

आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वो है बाज़ारवाद और उपभोक्तावाद का दौर। अब पहला प्रश्न यह कि इसका क्या मतलब हुआ? परिभाषा के हिसाब से यदि इसका अर्थ किया जाए तो वो ये होगा कि आज उपभोक्ता (यानी किसी भी वस्तु का उपयोग करने वाला) ही राजा है। खास बात यह है कि बाज़ारवाद के इस दौर में उपभोगता की जरूरत से आगे बढ़कर उसके आराम को केंद्र में रखकर ही वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है।

मोबाइल है तो यूज़र फ्रेंडली। कोई ऐप है तो उसका इस्तेमाल करने वाले की उम्र यानी बच्चे, युवा, अथवा वयस्क के मानसिक विकास,उसकी जरूरतों और क्षमताओं को ध्यान में रखकर उसे कस्टमर फ्रेंड्ली बनाया जा रहा है। अगर रोबोट है तो ह्यूमन फ्रेंड्ली। और पूंजीवाद के इस युग में तो मनुष्य के उपभोग के लिए समान बनाने वाली विभिन्न कंपनियां उसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं।

यहाँ यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इसके लिए (ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए) ये कंपनियां मार्केटिंग और पब्लिसिटी का इस हद तक सहारा ले रही हैं कि आज एडवरटाइजिंग अपने आप में एक तेजी से बढ़ता हुआ उद्योग बन चुका है।

अब दूसरा प्रश्न यह है कि इसके क्या मायने हैं? नहीं वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि पूंजीवाद के इस दौर में आप यानी ग्राहक एक राजा है। ये तो हमें एक ग्राहक के रूप में एहसास कराया जा रहा है लेकिन सत्य इसका उलट है। सत्य तो यह है कि उपभोगतावाद के इस दौर में हम बाज़रवाद के गुलाम बनकर रह गए हैं। क्यों चौंक क्यों गए न ?

चलिए जरा खुल कर बात करते हैं, इसे एक साधारण से उदाहरण से समझते हैं। सच बताइए जब हमारा बच्चा घर की रोटी या दाल चावल या सब्जी के बजाए मैगी की जिद करता है और हम यह जानते हुए कि हमारे बच्चे की सेहत के लिए मैगी ठीक नहीं है फिर भी हम मैगी खरीदते ही नहीं हैं बल्कि उसे खाने भी देते हैं तो क्या हम अपने मर्जी के राजा बनकर खरीदते हैं?

नहीं नहीं ऊपरी तौर पर नहीं बल्कि जरा गहराई और ईमानदारी से विषय पर सोचिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने बच्चे की जिद के आगे नतमस्तक हो रहे हैं तो माफ की जीयेगा आप गलत हैं। उस कंपनी ने आपके बच्चे को माध्यम बनाकर आपको अपना उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर कर दिया।

यह तो एक उदाहरण है। सोचेंगे तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कितने ही उदाहरण हमें मिल जाएंगे। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि उपभोक्तावाद के इस दौर में हमारी खाने पीने की आदतें प्रभावित हो रही हैं। बात इससे काफी आगे बढ़ चुकी है।

क्योंकि बात अब एक व्यक्ति के तौर पर, एक परिवार के तौर, पर एक समाज के तौर पर हमारे मूल्यों हमारी नैतिकता हमारे व्यक्तित्व हमारे आदर्शों के कभी ''कूल'' बनने के नाम पर तो कभी ''चिल आउट'' के नाम, पर कभी ''अपने लिए जीने'' के नाम पर तो कभी ''हाँ मैं परफेक्ट नहीं हूँ'' के नाम पर हमारे विचारों के प्रभावित होने तक पहुंच गई है।

परिणामस्वरूप सदियों से चली आ रही हमारी पारिवारिक और सामाजिक संरचना के मूल विचार भी प्रभावित होने लगे हैं। क्योंकि बाज़ारवाद के इस दौर में हम एक उपभोक्ता के रूप में

उत्पाद बनाने वाली कंपनियों के लिए पैसा कमाने का एक साधन मात्र हैं। एक बच्चे के रूप में, एक युवा के रूप में, एक पुरुष के रूप में एक महिला के रूप में एक बुजुर्ग के रूप में हम उनके लिए एक टारगेट कस्टमर से अधिक कुछ नहीं हैं। अपने लक्ज़री उत्पादों को बेचने के लिए किसी समाज को विलासिता की ओर आकर्षित करना बाज़ारवाद की स्ट्रेटेजी का हिस्सा होता है। कोई आश्चर्य नहीं आज इस तरह के वाक्य बहुत प्रचलन में हैं कि '' हाँ मैं परफेक्ट नहीं हूँ'' या ''मैं जैसी हूँ या जैसा हूँ मुझे वैसे ही स्वीकार करो''।

आज की पीढ़ी तो इन वाक्यों के प्रति आकर्षित भी होती हैं और सहमत भी। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जो बाज़ारवाद अपने भौतिक सुखों को देने वाली वस्तुओं को खरीदने के लिए हमें ''ये दिल मांगे मोर'' या ''डर के आगे जीत है'' जैसे संघर्षशील बनने का जज्बा देता है, वो ही बाज़रवाद जब बात हमारे व्यक्तित्व के विकास की आती है, हमारे नैतिक उत्थान की आती है, हमारे भीतर पारिवारिक या सामाजिक मूल्यों के विकास की आती है तो जो ''मैं जैसा हूँ या जैसी हूँ वैसा ही स्वीकार करो'' या फिर ''मैं एक साधारण मनुष्य हूँ भगवान नहीं'' जैसे विचार परोस देता है। वो बाज़ारवाद जब बच्चों और माँ से सम्बंधित कोई उत्पाद बेचता है तो अपने विज्ञापन में महिला को एक ''परफेक्ट मॉम'' से लेकर ''सुपर मॉम'' तक के रूप में दर्शाता है लेकिन वही बाज़ारवाद जब अपना कोई विलासितापूर्ण उत्पाद बेचता है तो महिला के लिए ''हाँ मैं परफेक्ट नहीं हूँ'' या फिर ''इट्स ओके नॉट टू बी परफेक्ट'' का विचार देता है।

अब आप कहेंगे कि इन वाक्यों में क्या दिक्कत है। इन वाक्यों में दिक्कत ये है कि ये वाक्य अधूरे हैं और अधूरे वाक्यों के रिक्त स्थान को हर कोई अपने हिसाब से भरने के लिए स्वतंत्र है। वैसे भी कहते हैं कि ज्ञान के न होने से इतना नुकसान नहीं होता जितना कि अधूरे ज्ञान होने से होता है। इन वाक्यों के साथ भी यही हो रहा है। सम्पूर्ण विश्व में आप किसी भी देश या संस्कृति में देखें तो हम पाएंगे कि एक मानव के रूप में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति निरंतर अपने उत्थान अपनी तरक्की की सोचता है। वो अपनी पूरी जीवन यात्रा में रोज कुछ नया सीखता है और आगे बढ़ता है। सोशल स्टेटस की बात हो या भौतिक सुखों की, मनुष्य आगे बढ़ना चाहता है। घर बड़ा चाहिए गाड़ी बड़ी चाहिए बैंक बैलेंस बड़ा चाहिए लेकिन जब व्यक्तित्व के विकास की बात आये नैतिक मूल्यों के विकास की बात आये तो इट्स ओके नॉट तो बी परफेक्ट! बात जब व्यक्तिगत या पारिवारिक या फिर सामाजिक मूल्यों की आये तो मैं भगवान नहीं इंसान हूँ!

जब इस प्रकार के अधूरे वाक्य समाज के आगे परोस दिए जाते हैं तो इन वाक्यों के रिक्त स्थान मनुष्य को, परिवार को और समाज को उनके मूल्यों से रिक्त कर देते हैं। फलस्वरूप उपभोक्तावाद की संस्कृति का मूल्य हम कुछ ऐसे चुकाते हैं कि हमारे नैतिक और सामाजिक मूल्य बाज़रवाद के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम इन वाक्यों के रिक्त स्थान को सही शब्दों और सही विचारों से भरे। हम कहें कि ''हां मैं परफेक्ट नहीं हूँ लेकिन मैं परफेक्ट बनने की कोशिश तो कर ही सकता हूँ।''

हम सोचें कि हाँ, इट्स ओके नॉट टू बी परफेक्ट ''बट इट्स नॉट ओके नॉट इवन ट्राय टू बिकम परफेक्ट।'' क्योंकि मानव जीवन का सार इन शब्दों में सिमटा है, '' इस धरती पर जन्म लेते समय हर जीव अज्ञानी होता है लेकिन अपने जीवन काल में ज्ञान अर्जित करके अपनी बुद्धि को ज्ञान और विवेक की नई ऊंचाइयों तक ले जाने का कर्म योग करने वाला जीव ही सही मायनों में मानव कहलाने का अधिकारी होता है।''

पर्वतारोहण एवं घुमक्कड़ी के शौकीनों के लिए पसंदीदा गंतव्य बना हिमाचल

शिमला। साहसिक गतिविधियों एवं घुमक्कड़ी के शौकीनों के लिए हिमाचल एक पसंदीदा गंतव्य है। प्रदेश सरकार राज्य में साहसिक गतिविधियों को चरणबद्ध ढंग से प्रोत्साहन प्रदान कर रही है ताकि इन गतिविधियों में रूझान रखने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो सके।

पैराग्लाइडिंग, जलक्रीड़ा, स्कीइंग आदि साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के अलावा, पर्वतारोहियों को सुविधा प्रदान करने के लिए भी सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। हिमाचल को प्रकृति ने मनमोहक दृश्यों से नवाज़ा है और राज्य में विशेष रूप से कुल्लू, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, किन्नौर, लाहौल-स्पीति तथा चंबा जिलों में कई लुभावने व आकर्षक स्थल हैं जो साहसिक खेल प्रेमियों को रोमांचक अनुभव के अलावा हिमालयी वनस्पतियों व वन्यजीवों के बारे में जानने का भी अवसर प्रदान करते हैं।

कुल्लू जिला की बात करें तो यहां स्थित लग घाटी को प्रकृति ने नैसगिंक सुन्दरता से नवाज़ा है। स्थानीय लोगों में 'कंस धार' या 'काईसधार' के नाम से प्रसिद्ध इस घाटी के अद्भुत नज़ारे हर किसी को आकर्षित करते हैं। यहां के बड़े-बड़े चारागाह और ब्रिटिश समय के फोरेस्ट हॉउस की आभा तत्कालीन शासकों की भव्यता को दर्शाती है। कुल्लू शहर की भीड़-भाड़ से परे यह स्थल 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और लगभग 3 से 5 घंटे का पैदल रास्ता (ट्रैक) तय कर यहां पहुंचा जा सकता है। इस पर्यटन स्थल से लग घाटी के खेत-खलियानों के शानदार व अद्भुत दृश्य पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं और प्रत्येक कदम पर छायाचित्र लेने के लिए विवश करते हैं। सूर्य की उष्मा से भरपूर 'काईस धार' मनोहारी दृश्यावलियों के लिए विख्यात है। घास के मैदान एवं घने जंगलों से आच्छादित पहाड़ियां यहां का मुख्य आकर्षण हैं।

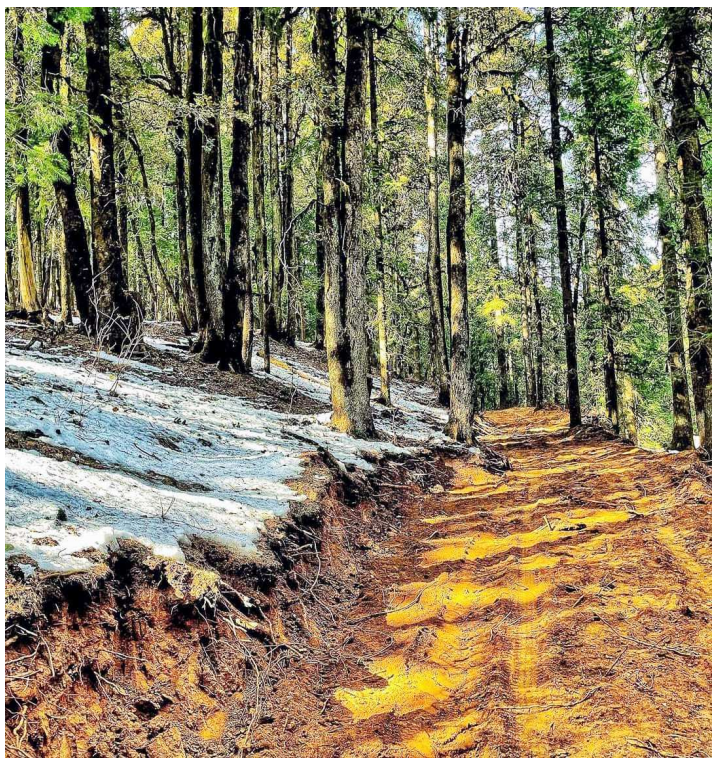

कैम्पिंग के लिहाज़ से भी यह जगह उत्तम है। यहां कुछ समय बिताने के बाद पर्यटक अगली सुबह चंबागाड़ टॉप पर जा सकते हैं और 3 घंटे के भीतर वापस विश्राम गृह लौट सकते हैं। यहां से कुपड़ी होकर हाथीपुर पहाड़ से मतासौर पहुंचा जा सकता है।

भुंतर हवाई अड्डे से कुछ दूरी पर शिंदोधार या शोंदोधार स्थित है। यह कुल्लू का प्रसिद्ध पर्यटन गंतव्य है जिसे क्षेत्र की अत्यन्त मनमोहक 'घाटियों' के लिए जाना जाता है। इसे 'गड़सा घाटी' भी कहा जाता है। यह अद्भुत स्थल दक्षिण में बंजार तहसील, पश्चिम की ओर द्रंग और दक्षिण की ओर सिराज तहसील से घिरा हुआ है। लगभग 1189 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह एक अति सुंदर गांव है। भुंतर से शमशी सर्किट की इस घाटी में ऊंचे वन मैदान हैं। तितलियों और पक्षियों से भरे हरे-भरे घास के खुले मैदान के दृश्य देखते ही बनते हैं जिससे मन में नई ऊर्जा का संचार होता है। यहां के समीपवर्ती हवाई और दियार गांव भी प्रदेश में आने वाले पर्यटकों के लिए प्रकृति का अतुलनीय उपहार हैं।

कुल्लू जिले की सिराज घाटी हिमाचल प्रदेश के सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक है। हरे-भरे जंगल व वनस्पतियों से भरपूर घास के मैदान, यहां की स्फटिक आभा, पहाड़ी झरनों की धवल धाराएं और चारों ओर शानदार बर्फ से ढके पहाड़ इसे विश्व का एक अविस्मरणीय हिस्सा बनाते हैं।

सिराज क्षेत्र जलोड़ी दर्रे से मंडी जिले के जंजैहली में शिकारी देवी तक फैला है और इस क्षेत्र में बंजार-शिमला मार्ग पर स्थित सुंदर गांव 'जिभी' लोगों के लिए वर्षभर आकर्षण का केन्द्र रहता है।

यहां आसपास के पहाड़ चीड़ और देवदार के जंगलों से भरे हुए हैं। यह क्षेत्र ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क से केवल एक घंटे की दूरी पर स्थित है। इस दूरस्थ एवं अनुछई मनोरम घाटी से पर्यटक स्वर्गिक आनंद की अनुभूति पाते हैं।

यहां के अन्य खूबसूरत स्थलों में खनाग, जलोड़ी दर्रा, सोझा और बंजार भी शामिल हैं। खनाग घने जंगलों के बीच एक हिमालयी घास का मैदान है। जलोड़ी पर्वत की चोटी से बर्फ से ढकी चोटियों के कभी न भूलने वाले नजारे दिखाई देते हैं।

यहां समीप ही करीब 10,500 फीट की ऊंचाई पर श्रृंगा ऋषि मंदिर स्थित है। इसी घाटी में सियोलसर झील भी स्थित है। यह दोनों स्थान इसे ट्रेकिंग के लिए पर्यटकों का पसंदीदा गंतव्य बनाते हैं। जलोड़ी दर्रे की यह पूरी घाटी देवदार के ऊंचे वृक्षों से घिरी हुई है।

साहसिक खेल प्रेमी शिमला से गुम्मा, लुहरी, आनी से जलोड़ी और आगे कुल्लू होते हुए ट्रेकिंग कर सकते हैं। शिमला ग्रामीण और कुल्लू घाटी की सुंदरता का आनंद लेते हुए इस ट्रेक को पार करने में लगभग एक सप्ताह का समय लगेगा।

पार्वती घाटी में खीरगंगा भी एक मनमोहक पर्यटन गंतव्य है जहां पहुंचने पर भगवान शिव के अवस्थित होने की अनुभूति होती है। खीरगंगा को प्रकृति ने अपार सुंदरता से नवाज़ा है और आगंतुकों को मंत्रमुग्ध करता है। यहां की यात्रा में गर्म पानी के झरने और पार्वती घाटी के शानदार दृश्य पर्यटकों को खूब लुभाते हैं। यहां के कुछ गर्म पानी के झरनों की अद्भुत कहानियां हैं, वहीं कुछ अपनी रहस्यमयी प्रकृति के लिए भी लोकप्रिय हैं।

खीरगंगा के लिए बरशैणी गांव से लगभग 24 किलोमीटर की पैदल दूरी तय कर पहुंचा जा सकता है। उतार-चढ़ाव से भरपूर इस रास्ते से खीरगंगा पहुंचने में एक दिन लगता है। हरे-भरे पहाड़ों, ऊंचे झरनों, वनस्पतियों और जैव विविधता के लिए विख्यात पार्वती घाटी आगंतुकों को रोमांचित करती है।

वर्तमान प्रदेश सरकार राज्य के प्रसिद्ध पर्यटन गंतव्यों को विकसित करने और साहसिक खेल प्रेमियों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। इससे राज्य में पर्यटकों की आमद बढ़ने के साथ ही यहां के युवाओं को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर रोज़गार के अवसर भी सृजित होंगे और पर्यटक गाईड के रूप में भी कार्य कर सकेंगे।

सुगंधित फूलों की खेती से फैली खुशियों की मुस्कान

शिमला। सुगंधित फूलों का नाम आते ही खुशबू का अहसास होने लगता है, लेकिन जब इन्हीं फूलों की खेती से कमाई के साथ स्वरोजगार मिलने लगे तो चेहरे पर खुशियों की मुस्कान बरबस ही आ जाती है। सुगंधित फूलों की खेती करके इसे साबित किया है, चंबा जिले के विकासखंड तीसा की ग्राम पंचायत सेईकोठी के प्रगतिशील किसान लोभी राम और ग्राम पंचायत हरतवास के उन्नत किसान यशवंत सिंह ने। सुगंधित फूलों की खेती में इन दोनों किसानों ने अपनी अलग ही पहचान बनाई है।

अरोमा मिशन के अंतर्गत जिला प्रशासन के सहयोग से आईएचबीटी पालमपुर द्वारा लैवंडर पौधे वितरित किये गये। क्षेत्र में लैवेंडर की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि किसान अपनी आमदनी को बढ़ा सकें और स्वरोजगार की ओर बढ़ सकें।

ग्राम पंचायत सेईकोठी के प्रगतिशील किसान लोभी राम कहते हैं कि वे सुगंधित पौधों की खेती लगभग 22 साल से करते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 5 सालों से लैवंडर की खेती करने में रुचि दिखा रहे हैं, जितना लाभ मुझे लैवेंडर की खेती करने से हुआ है उतना अन्य सुगंधित पौधों की खेती से नहीं हुआ।

उन्होंने कहा कि लैवेंडर की खेती ऐसी है कि जिसके पौधे को ना ही जंगली जानवर, बंदर इत्यादि खराब करते है और ना ही किसी भी प्रकार की खाद की जरूरत पड़ती है।

उन्होंने कहा कि लैवंडर के फूल, तेल, नर्सरी के साथ-साथ लेवेंडर के पत्ते भी आमदनी का साधन है, इस खेती से काफी लाभ प्राप्त किया है।

लैवेंडर की खेती को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने और लोगों को भी प्रोत्साहित किया है। उन्होंने जम्मू और कश्मीर में भी इस खेती को प्रोत्साहित करने के लिए वहां के लोगों का सहयोग किया है।

लोभी राम कहते हैं कि लैवेंडर की खेती के साथ उन्होंने गुलाब के पौधों की इंटर क्रॉपिंग भी की है। उन्होंने कहा कि गुलाब तेल की भी बाजार में काफी मांग है और जिसकी कीमत लगभग 20 से 30 लाख रुपए प्रति किलोग्राम है। इसके साथ साथ गुलाब के पौधे और उनकी कलमें भी अच्छी कीमत पर बिकती है।

उन्होंने कहा कि उद्यान विभाग के साथ-साथ अरोमा मिशन के अंतर्गत हमें लैवेंडर की खेती को बढ़ावा देने के लिए मदद मिल रही है। मिशन के अंतर्गत पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिससे किसानों को अधिक लाभ मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि किसान अधिक से अधिक इस खेती से जुड़ते हैं तो वह अच्छा लाभ कमा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि मैंने ऑयल डिस्टिलेशन यूनिट भी स्थापित किया है, जहां पर वह खुद ही तेल निकालते हैं। लैवेंडर के तेल की कीमत 15 से 20 हजार रुपये प्रति किलोग्राम है।

उन्होंने कहा कि 4 हेक्टेयर भूमि पर सुगंधित पौधों की खेती कर रहे हैं। इस कार्य में चुराह के ही लगभग 40 किसान हमारे साथ जुड़े हैं। उन्होंने यह भी कहा कि किन्नौर में भी लैवेंडर के पौधे लगाये गये हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि पिछले साल मैंने तेल बेचकर लगभग 26 लाख की आमदनी अर्जित की है। इसके अतिरिक्त कुठ की खेती भी कर रहे हैं जिसके तेल की कीमत लगभग 2 लाख रुपए पर किलोग्राम है और उन्होंने लगभग 400 बीघा में हर्बल की खेती की है।

उन्होंने बताया कि सुगंधित पौधों की खेती से वे सालाना करोड़ों रुपए का कारोबार कर रहे हैं।

इसके साथ ही ग्राम पंचायत हरतवास के यशवंत सिंह कहते हैं कि वे 2006 से लैवेंडर की खेती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रगतिशील किसान लोभी राम के साथ मिलकर पिछले 3 सालों में 25 से 30 हजार पौधों को तैयार किया है। उन्हें इस खेती से काफी लाभ हो रहा और वे इस काम को बड़ी ही लगन और मेहनत से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लैवेंडर के पौधे का कोई भाग व्यर्थ नहीं जाता है और वह साल में लैवेंडर की खेती की तीन फसलें निकाल लेते हैं। जून माह में लैवेंडर की भरपूर फसल होती है अक्टूबर माह और फरवरी माह में भी फसल निकलती है।

लैवंडर के एक क्विंटल पौधों से लगभग एक से डेढ़ किलोग्राम तेल निकलता है। जिसकी कीमत लगभग 15 से 20 हजार रुपए मिल जाती है और घर द्वार पर ही तेल की बिक्री हो जाती है। जिससे हमें काफी लाभ प्राप्त हो रहा है।

उद्यान विभाग के फैसिलिटेटर राहुल राठौर बताते हैं कि अरोमा मिशन के तहत विकासखंड तीसा में प्रगतिशील किसान लोभी राम लैवेंडर की खेती से काफी मुनाफा कमा रहे हैं। इसके साथ साथ अन्य किसानों को भी इस खेती के प्रति अपनी रूचि दिखाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में हाल ही में मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री के साथ प्रदेश में

सड़क अधोसंरचना के विकास को लेकर हुई चर्चा के दौरान उठाये गये विभिन्न मामलों की प्रगति की समीक्षा की गयी। दिल्ली में प्राधिकरण के सदस्य मनोज कुमार इस बैठक में विशेष रूप से उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सड़क सम्पर्क को सुदृढ़ करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण प्रदेश में संचालित की जा रही फोरलेन सड़क परियोजनाओं को तीव्र गति प्रदान करे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वन स्वीकृतियों सहित अन्य सभी प्रक्रियाओं को सरल एवं समयबद्ध किया है। राज्य सरकार सड़कों के विकास में प्राधिकरण को हरसंभव मदद करेगी।

उन्होंने कहा कि लगभग 10 हजार करोड़ रुपए की शिमला से मटौर तथा लगभग 12 हजार करोड़ रुपए की पठानकोट से मंडी तक फोरलेन सड़क तैयार करने के लिए प्राधिकरण सैद्धांतिक तौर पर सहमत हो गया है। इसके साथ ही प्रदेश में सड़कों के विस्तारीकरण के दौरान पहाड़ों की कटाई से होने वाले भू-स्खलन एवं पत्थर इत्यादि गिरने से रोकने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एक कांसेप्ट पेपर तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि बारिश में इन सड़कों पर पत्थर एवं मलबा इत्यादि गिरने से रोकने की परियोजना पर एनएचआई के माध्यम से लगभग 300 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि सड़क सम्पर्क बेहतर होने से यहां पर्यटकों की आमद बढ़ेगी और उन्हें बेहतर सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है और इस दृष्टि से भी पठानकोट-मंडी व शिमला-मटौर फोरलेन सड़क परियोजनाएं महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि मंडी शहर के समीप 19 किलोमीटर के भाग को छोड़कर पठानकोट-मंडी फोरलेन सड़क परियोजना के विभिन्न पैकेज की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट शीघ्र तैयार की जाए।

इसके अतिरिक्त उन्होंने हमीरपुर बाईपास की डीपीआर जल्द तैयार करने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विद्युत चालित वाहनों के संचालन को भी बढ़ावा दे रही है। ऐसे में प्राधिकरण इन फोरलेन सड़क परियोजनाओं में विद्युत चालित वाहनों के लिए उचित दूरी पर चार्जिंग स्टेशन का भी प्रावधान रखे। उन्होंने कहा कि सड़कों की दूरी कम करने तथा लोगों के बहुमूल्य समय की बचत के उद्देश्य से यहां सुरंग निर्माण की संभावनाएं भी तलाशी जाएं।

उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की गयी भूमि का मुआवज़ा प्रदान करने के लिए प्रक्रिया तेज की गयी है और सबंधित उपायुक्तों को इस बारे में आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सहयोग से बस पोर्ट का व्यवसायिक मॉडल तैयार करने तथा राज्य में रोप-वे परियोजनाओं विशेष तौर पर हिमानी चामुंडा एवं बिजली महादेव रोप-वे के विकास में एनएचएआई से आवश्यक सहयोग पर भी बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त फोरलेन सड़कों के मैदानी क्षेत्रों वाले भागों में वाहनों की गति सीमा बढ़ाने, इन सड़क मार्गों के किनारे वे-साईड सुविधाएं उपलब्ध करवाने तथा राजस्व आवंटन से संबंधित मामलों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, प्रधान सचिव आर.डी. नजीम व ओंकार चंद शर्मा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय अधिकारी अब्दुल बासित और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

चन्द्र कुमार ने केन्द्रीय पशुपालन मंत्री से भेंट की

शिमला/शैल। कृषि एवं पशुपालन मंत्री चन्द्र कुमार ने नई

दिल्ली में केन्द्रीय पशुपालन मंत्री परशोत्तम रूपाला से भेंट की।

इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में पशुपालन व दुग्ध विकास के संबंध में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से पशु चिकित्सा संस्थानों के सुदृढ़ीकरण, गद्दी-गुज्जरों के विकास के लिए योजना तथा पशुधन के लिए बीमा सुविधा आरंभ करने का आग्रह किया।

उन्होंने केन्द्र सरकार से प्रदेश के लिए पर्याप्त संख्या में मुंह-खुर रोग प्रतिरोधी टीके उपलब्ध करवाने का आग्रह किया।

चन्द्र कुमार ने अवगत करवाया कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए दुग्ध उत्पादन तथा पशुपालन से संबंधित गतिविधियों को विशेष प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग एक हजार करोड़ रुपये की बहुआयामी योजनाएं आरंभ करने की दिशा में राज्य सरकार काम कर रही है। उन्होंने प्रदेश में दुग्ध सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण के लिए उठाए जा रहे विभिन्न कदमों की जानकारी भी दी।

केन्द्रीय मंत्री ने प्रदेश में दुग्ध विकास गतिविधियों को प्रोत्साहित करने तथा अन्य योजनाओं के दृष्टिगत के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।

इस अवसर पर शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया, निदेशक पशुपालन प्रदीप शर्मा, वूलफेड के प्रबंध निदेशक विजय ठाकुर और पशुपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

सचिवालय में प्रतिदिन तथा ओक ओवर में दो दिन आमजन से मिलेंगे मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि जनता की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू आम लोगों तथा विभिन्न प्रतिनिधिमण्डलों से प्रतिदिन सांय 6.00 बजे से 7.00 बजे तक राज्य सचिवालय में मिलेंगे।

उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त आम जनता प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को प्रातः 9.00 बजे से प्रातः 11.00 बजे तक मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ओक ओवर में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिल सकती है, जबकि पार्टी कार्यकर्ता प्रत्येक सोमवार और गुरुवार सायं 5.00 बजे से 6.00 बजे तक सचिवालय में मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं।

प्रवक्ता ने कहा कि विधायक, पूर्व विधायक और अन्य जन प्रतिनिधि मुख्यमंत्री से प्रत्येक कार्य दिवस पर दोपहर 3.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक सचिवालय में मिल सकते हैं।

उन्होंने कहा कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रवास के दौरान निरंतर लोगों से भेंट करते हैं और उनकी समस्याओं एवं मांगों का मौके पर समाधान करने की व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं।

मुख्यमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में राज्य सतर्कता ब्यूरो के पौधरोपण अभियान का शुभारंभ किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य सतर्कता ब्यूरो द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित पौधरोपण अभियान का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर उन्होंने सतर्कता ब्यूरो के मुख्यालय के समीप सरू प्रजाति के 'क्रिप्टोमेरिया'

का पौधा रोपित किया।

इस वर्ष महिला दिवस की विषयवस्तु डिजिट ऑल लैंगिक समानता में नवोन्मेष एवं प्रौद्योगिकी है। इस पौधरोपण अभियान की थीम 'नागरिकों की सुरक्षा के साथ पर्यावरण की रक्षा' रखी गयी है।

मुख्यमंत्री ने इस अभियान की सराहना करते हुए कहा कि महिलाओं ने अपनी प्रत्येक जिम्मेवारी एवं कर्तव्य का सदैव पूर्ण निष्ठा से निर्वहन किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे अभियानों से पर्यावरण संरक्षण के सरकार के प्रयासों को भी बल मिलता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पर्यावरण प्रहरी के रूप में महिलाएं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए समाज को भी जागरूक करेंगी। उन्होंने कहा कि हमें पुरुष प्रधान मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है और इसके लिए कांग्रेस की सरकारों ने समय-समय पर ठोस कदम उठाये हैं। इससे पिछले तीन-चार दशकों में महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि महिलाएं परिवार के साथ-साथ समाज को भी दिशा देती हैं। उन्होंने महिला सशक्तिकरण में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी तथा कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी के योगदान को भी याद किया।

इस अवसर पर महिलाओं की भूमिका विषय पर एक प्रस्तुतिकरण भी दिया गया।

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरूद्ध सिंह, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी तथा विधायक हरीश जनारथा ने भी पौधरोपण कार्यक्रम में भाग लिया।

इससे पहले, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने स्वागत संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार के प्रोत्साहन एवं दिशा-निर्देशन में पुलिस विभाग महिलाओं व बच्चों के प्रति अपराधों पर रोक लगाने के लिए प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग कर रहा है। उन्होंने पुलिस विभाग में महिला अधिकारियों को केंद्रीय भूमिका में लाने के लिए प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हुए इसका विस्तृत ब्यौरा भी दिया।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सतवंत अटवाल ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया और इस अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की।

इस अवसर मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा और पुलिस विभाग व सतर्कता ब्यूरो के उच्चाधिकारी भी उपस्थित थे।

परिवहन विभाग ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने का आग्रह किया

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग ने प्रदेश के लोगों और पर्यटकों से वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।

परिवहन विभाग के निदेशक अनुपम कश्यप ने बताया कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के कारण प्रतिवर्ष सैंकड़ों लोगों की मृत्यु होती है और हजारों लोग घायल हो जाते हैं। इसका सामाजिक परिवेश के साथ-साथ आर्थिक व्यवस्था पर भी कुप्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 21.27 लाख वाहन पंजीकृत हैं जिनमें से नौ लाख से अधिक दो पहिया वाहन है। अधिकांश दो पहिया वाहनों का उपयोग युवाओं द्वारा किया जाता है। तेज रफ्तार और हेलमेट का प्रयोग नहीं करने से सड़क दुर्घटना व गंभीर चोटों का जोखिम और भी बढ़ जाता है।

उन्होंने लोगों से वाहन चलाते समय सीमित गति, हेलमेट व सीट बेल्ट का प्रयोग करने के साथ-साथ मोबाईल फोन का इस्तेमाल नहीं करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि शराब पीकर वाहन चलाना एक दंडनीय अपराध है और नशा सेवन के उपरान्त वाहन चलाने से दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। उन्होंने लोगों से समय-समय पर वाहन की जांच करवाने, वाहन चलाते समय संयमित व्यवहार करने, स्कूलों के आसपास बहुत धीमी गति में वाहन चलाने, ओवरटेक से बचने और सभी यातायात नियमों का पालन करने का आग्रह किया।

परिवहन निदेशक ने कहा कि कुछ लोग वाहनों में सफर के दौरान सनरूफ से बाहर निकलते हैं यह भी यातायात नियमों के खिलाफ है और सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक है।

उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा लोगों को यातायात नियमों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए निरंतर जागरूकता अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत सहयोग का आग्रह करते हुए कहा कि यातायात नियमों का पालन करने से न केवल अपनी बल्कि अन्य लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है।

मुख्यमंत्री ने आईजीएमसी में 30.90 करोड़ रुपए से निर्मित बहुमंजिला ट्रॉमा ब्लॉक का लोकार्पण किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंदिरा गांधी राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय (आईजीएमसी) के नए ओ.पी.डी. ब्लॉक में लगभग 30.90 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ट्रॉमा ब्लॉक का लोकार्पण किया।

ट्रॉमा ब्लॉक के इस बहुमंजिला भवन में फिजियोथैरेपी वार्ड, स्पेशल वार्ड, आपातकालीन चिकित्सा इकाई, गहन देखभाल इकाई (आईसीयू) बेड, आईसोलेशन वार्ड सहित सीटी स्कैन, एक्स-रे, सैंपल एकत्रीकरण केंद्र तथा पैथोलॉजी प्रयोगशाला की सुविधा उपलब्ध करवायी गयी है। घायलों व गंभीर रोगियों के उपचार संबंधी वरीयता के लिए यहां अलग व्यवस्था की गयी है। अन्य आपात सेवाओं के साथ-साथ यहां पर डॉक्टर, नर्स तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कक्ष, रोगियों के बैठने के लिए स्थान तथा अन्य जनोपयोगी सेवाएं भी उपलब्ध होंगी।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर नए ओपीडी परिसर का अवलोकन किया और रोगियों, उनके परिचारकों तथा अस्पताल स्टाफ के साथ संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि इस ब्लॉक के निर्माण से लोगों को गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवाएं मिलने के साथ साथ यहां सेवाएं देने वाले डॉक्टरों एवं अन्य पैरा मेडिकल स्टाफ को कार्य करने के लिए उचित वातावरण भी प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी में मशीनरी तथा उपकरणों के लिए 12 करोड़ रूपये व्यय किए जा रहे हैं। यह उपकरण व मशीनरी, संस्थान के सर्जरी, ऑर्थोपीडिक्स, न्यूरो-सर्जरी, रेडियोलॉजी तथा एनस्थिसिया विभाग में उपयोग में लाये जायेंगे।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए नए दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रही है। प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में आपातकालीन

चिकित्सा को सृदृढ़ करने के लिए अलग से विभाग स्थापित किए जाएंगे। इसमें प्रत्येक 6 बिस्तर में दाखिल मरीजों की सुविधा के लिए एक नर्स तथा 10 बिस्तर में मरीजों की सुविधा के लिए चिकित्सक की व्यवस्था होगी। गहन देखभाल केंद्र (आईसीयू) में प्रत्येक बिस्तर में मरीजों की सुविधा के लिए एक नर्स की व्यवस्था की जाएगी। यहां विशेषज्ञ चिकित्सा भी तैनात किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए अनेक कदम उठा रही है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में रोबॉटिक सर्जरी की सुविधा प्रदान की जाएगी ताकि लोगों को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें। इसके अतिरिक्त इन स्वास्थ्य संस्थानों में अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए 5-जी प्रौद्योगिकी का समावेश किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों को उनके घर-द्वार के समीप उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रत्येक मेडिकल ब्लॉक में आधुनिक प्रौद्योगिकी युक्त हाईटैक अस्पताल स्थापित किए जाएंगे।

चिकित्सा महाविद्यालय प्रबंधन ने मुख्यमंत्री को सम्मानित भी किया।

इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ.(कर्नल) धनी राम शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के ओजस्वी नेतृत्व में स्वास्थ्य की आधारभूत संरचना सुदृढ़ करने के लिए विशेष कदम उठा रही है। ग्राम स्तर पर बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

विधायक हरीश जनारथा ने आईजीएमसी में लोगों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, सचिव, स्वास्थ एम. सुधा देवी, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा, आईजीएमसी की प्रधानाचार्या डॉ. सीता ठाकुर, चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राहुल राव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

भाजपा विधायक दल ने लाखो की संख्या में कांग्रेस के खिलाफ हस्ताक्षर राज्यपाल को सौंपे

शिमला/शैल। भाजपा विधायक दल ने प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में लाखों की तादात में हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता द्वारा किए गए हस्ताक्षर सौंपे।

कांग्रेस ने जिस प्रकार से 900 से अधिक सरकारी संस्थान बंद कर दिए जनता में इसको लेकर बहुत रोष है, जो इन लाखो हस्ताक्षरों के माध्यम से दिखता है।

विधायक दल में सभी मंडलों के आये हस्ताक्षर राज्यपाल को सौंपे और एक ज्ञापन भी दिया।

जयराम ठाकुर और विधायक दल द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा हिमाचल प्रदेश स्वच्छ राजनीति, सुशासन एवं स्वस्थ लोकतंत्र प्रणाली का द्योतक है। हिमाचल का इतिहास रहा है कि जब भी प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होता है तो नई सरकार पूर्व सरकार के कार्यों को आगे बढ़ाकर प्रदेशहित व जनहित में कार्य करती है परन्तु यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार द्वारा पूर्व भाजपा सरकार के समय जनहित में कैबिनेट मंजूरी के बाद एवं बजटीय प्रावधान के साथ विभिन्न विभागों के जो सरकारी संस्थान खोले गए थे, उन्हें राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से बिना कैबिनेट की मंजूरी के बंद कर दिया गया है, जो कांग्रेस पार्टी की संकीर्ण एवं दूषित मानसिकता का परिचायक है। वर्तमान सरकार की इस तानाशाहीपूर्ण कार्यशैली से प्रदेश की जनता को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

पालमपुर में खण्ड विकास कार्यालय खोला जाएगा: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट में आवश्यक प्रावधान कर पालमपुर में खण्ड विकास कार्यालय खोलने की घोषणा की। इससे क्षेत्र के लोगों को सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री पालमपुर में राज्य स्तरीय होली मेले के अवसर पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पालमपुर में बस अड्डे के समीप पार्किंग सुविधा विकसित करने की घोषणा भी की, जिससे स्थानीय

लोगों और पर्यटकों को सुविधा प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि पालमपुर को आईटी हब के रूप में विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांगड़ा जिला को 'पर्यटन राजधानी' के रूप में विकसित किया जा रहा है। इससे क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ बुनियादी ढांचे को भी मज़बूत किया जा रहा है। कांगड़ा में हेलीपोर्ट बनाने के साथ ही गग्गल में मौजूद हवाई अड्डे के विस्तार की प्रक्रिया भी जारी है। इस हवाई अड्डे से न केवल कांगड़ा बल्कि पूरे राज्य को लाभ प्राप्त होगा।

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार 'व्यवस्था परिवर्तन' के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। अनाथ बच्चों को 'राज्य के बच्चे' का दर्जा दिया गया है। इनके लिए मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना आरंभ की गयी है जिसके तहत राज्य सरकार 6000 अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन बच्चों की शिक्षा तथा जेब खर्च के लिए धनराशि उपलब्ध करवाएगी। इसके अतिरिक्त वर्ष में एक बार उनको भ्रमण करवाने के लिए हवाई यात्रा एवं तीन सितारा होटल में ठहराने के लिए पर्याप्त धनराशि भी उपलब्ध करवाएगी।

उन्होंने कहा कि मंत्रिमण्डल की पहली बैठक में ही पुरानी पैंशन बहाल कर दी गयी है। इससे राज्य के 1.36 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपनी पहली गारंटी को पूरा किया है और शेष गारंटी को भी चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राज्य स्तरीय पालमपुर होली मेले की स्मारिका का विमोचन भी किया।

हिमाचल में निवेश मित्र वातावरण प्रदान करने के लिए राज्य सरकार कृतसंकल्प:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) हिमाचल प्रदेश के वार्षिक अधिवेशन-2022-23 तथा हिमाचल प्रदेश के लिए आगामी पांच वर्षों का विकास एजेंडा विषय पर आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता की। इसमें निवेश को सुविधा, रोजगार सृजन एवं विकास को गति देते हुए उन्नत हिमाचल पर चर्चा की गयी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ कार्य कर रही है और प्रदेश में निवेश मित्र वातावरण प्रदान करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उद्यमियों का उन्नत हिमाचल के निर्माण में अहम योगदान है और राज्य सरकार उनकी समस्याओं का त्वरित निदान कर उन्हें बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योगों की स्थापना तथा अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धारा 118 से संबंधित स्वीकृतियों को समयबद्ध करने के लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है। इसके लिए एक इन्वेस्टमेंट ब्यूरो की स्थापना भी की जा रही है जिसके माध्यम से निवेश के लिए सभी स्वीकृतियां एक ही स्थान पर प्राप्त हो सकेंगी। प्रदेश में उद्योगों को न्यूनतम दरों पर 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवायी जा रही है। उन्होंने आग्रह किया कि प्रदेश में उद्योगों की स्थापना को भी समयबद्ध करें ताकि उद्योग जगत एवं प्रदेश तथा यहां की जनता को शीघ्र इनका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत खुले मन से कार्य करे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले बजट में हिमाचल को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए सरकार का दृष्टिकोण नजर आएगा। राज्य सरकार पर्यटन क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को वर्ष 2025 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके दृष्टिगत आगामी तीन वर्षों में राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन अपनाने का लक्ष्य रखा है और यह उद्योगों की जरूरतों को भी पूरा करेगा। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन को प्राथमिकता प्रदान करते हुए इसके लिए आधारभूत ढांचा भी विकसित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य में रेल सम्पर्क तथा सड़कों का विस्तारीकरण करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। इससे उद्योगों को कच्चे माल की ढुलाई एवं तैयार उत्पादों के परिवहन में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हमेशा उद्योगों के हितों की रक्षा के लिए कृतसंकल्प है और सरकार के सक्रिय हस्तक्षेप से हाल ही में बरमाणा तथा दाड़लाघाट में उपजे ढुलाई दरों के विवाद का सर्वमान्य हल संभव हुआ है।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर धारा 118 से संबंधित विभिन्न मामलों को लेकर उद्योगपतियों से संवाद भी किया और मौके पर ही उनके निस्तारण के लिए निर्देश भी जारी किए।

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए कार्य कर रही है। छोटे कारोबारियों से लेकर बड़े उद्योगों को समय-समय पर विभिन्न सुविधाएं एवं लाभ प्रदान किए जा रहा हैं। ऊना में बल्क ड्रग पार्क एवं नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए हाल ही में मुंबई में संपन्न फार्मा एकस्पो में लगभग 2110 करोड़ रुपए के आशय पत्रों के समझौते हस्ताक्षरित किए गए हैं। जीएसटी पूर्व के मामलों में राहत देते हुए वन टाइम सेटलमेंट से लगभग 50 हजार छोटे कारोबारियों को लाभ दिया गया है।

ग्रामीण विकास मंत्री अनिरूद्ध सिंह ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए।

सीआईआई हिमाचल के निवर्तमान अध्यक्ष सुबोध गुप्ता ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और उद्योग जगत से संबंधित विभिन्न गतिविधियों एवं उनकी समस्याओं से अवगत करवाया।

सीआईआई हिमाचल के नवनियुक्त अध्यक्ष गगन कपूर ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

इस अवसर पर विधायक इंद्रदत लखनपाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, प्रधान सचिव उद्योग आर.डी. नजीम, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, निदेशक उद्योग राकेश प्रजापति, मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया, निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क किरन भड़ाना, ओएसडी गोपाल शर्मा सहित सीआईआई के पदाधिकारी एवं अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

आने वाला हर चुनाव सरकार की परीक्षा होगा संगठन की नही

- भाजपा की आक्रामकता के साथ अपनों के सुर मिलना खतरे का संकेत
- कुलदीप राठौर और रवि ठाकुर के ब्यान चिन्ताजनक

शिमला/शैल। सरकार बनने के बाद आने वाले हर चुनाव सरकार के कामकाज की परीक्षा बन जाता है। यह एक स्थापित सच है। सरकार बनने के बाद संगठन की भूमिका सीमित रह जाती है। अभी सरकार को सत्ता में तीन माह हुए हैं और विपक्षी भाजपा सरकार पर अभी से आक्रामक हो गयी है। बल्कि यहां तक कहा जाने लग पड़ा है कि यह सरकार चल नहीं पायेगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के तेवर आये दिन कड़े होते जा रहे हैं। विपक्ष लोकसभा की चारों सीटें फिर जीतने का दावा कर रहा है। विपक्ष की आक्रामकता सरकार के फैसलों का प्रतिफल है। बल्कि यह कहा जा रहा है कि इन सरकार के फैसलों ने विपक्ष को पूरे पांच वर्षों के लिए पहले ही दिन मुद्दे थमा दिये हैं। भाजपा की आक्रामकता उस समय गंभीर हो जाती हैं जब कांग्रेस के अपने ही विधायक सरकार के फैसलों और नीतियों पर सवाल उठाने लग जायें। सरकार ने पहले ही दिन जो संस्थान डिनोटिफाई किये थे उन पर अब कुछ अपने भी रोष प्रकट करने लग गये हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर सभी संस्थानों को डिनोटिफाई करने के पक्ष में नहीं हैं। बल्कि कांग्रेस के वह सभी विधायक जिनके क्षेत्रों में कुछ खुला था और अब अपनी ही सरकार आने पर बन्द हो जाये तो वह अपने ही लोगों को जवाब देने की स्थिति में नहीं रह जाते हैं। क्योंकि जब सरकार गारंटीयां पूरी करने के लिये धन का प्रबन्ध कर सकती है तो संस्थान चलाने के लिये क्यों नहीं। संस्थान तो सार्वजनिक हित की परिभाषा में आते हैं। लेकिन गारंटीयां सार्वजनिक हित में नहीं होती हैं। सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन करने का दावा कर रखा है इस दावे के तहत ही अधिकारियों/कर्मचारियों के तबादले नहीं किये जा रहे हैं। लेकिन जहां पर रिक्त स्थान हैं या जो कर्मचारी कठिन एरिया में अपना कार्यकाल पूरा करा चुका है वह तो तबादला चाहेगा ही और उसके स्थान पर किसी दूसरे को तबादला करके ही भेजा जायेगा। लाहौल स्पीति के विधायक अपना रोष सार्वजनिक तौर पर प्रकट कर चुके हैं। उनका रोष इस बात का प्रमाण है कि सब अच्छा नहीं चल रहा है। हमीरपुर में कर्मचारी चयन आयोग बन्द कर दिये जाने के बाद जो युवा परेशान हुए हैं वह दिल्ली तक पैदल मार्च करके कांग्रेस हाईकमान के सामने अपना पक्ष रखने जा रहे हैं। सरकार ने ओल्ड पैन्शन स्कीम बहाल करने का फैसला ले लिया है लेकिन विभिन्न निगमों/बोर्डो के कर्मचारी इस फैसले से बाहर रह गये हैं और अन्ततः उन्हें भी आन्दोलन के रास्ते पर यदि आना पड़ा तो ओल्ड पैन्शन से होने वाला राजनीतिक लाभ शून्य होकर रह जायेगा। संस्थान बन्द करने के फैसले के खिलाफ भाजपा पहले ही उच्च न्यायालय जा चुकी है। मुख्य संसदीय सचिव के फैसले को भी चुनौती मिलने जा रही है। यदि सरकार समय रहते अपने फैसलों पर निष्पक्षता से समीक्षा नहीं करती है तो इन फैसलों का प्रभाव आने वाले नगर निगम शिमला के चुनाव पर पड़ना तय है। इस समय संस्थानों को डिनोटिफाई करने और मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियों वाले दो ऐसे फैसले हैं जिन पर कानूनी तौर पर सरकार का पक्ष कमजोर है और यह दोनों मामले उच्च न्यायालय में हैं। इन पर इस वर्ष के अन्त तक फैसले आने की संभावना मानी जा रही है। अभी बजट सत्र में मंत्रियों के रिक्त पद नहीं भरे गये हैं। यह पद लोकसभा चुनाव से पहले भरने आवश्यक हो जायेंगे। क्योंकि इस समय पन्द्रह विधायकों वाले जिले से केवल एक ही मंत्री है। बिलासपुर को कोई प्रतिनिधित्व मिला नहीं है। जातीय समीकरणों के दृष्टिकोण से भी मंत्रिमण्डल संतुलित नहीं है। आने वाले समय में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाना राजनीतिक अनिवार्यता हो जायेगी। यदि यह संतुलन न बन पाया तो लोकसभा चुनाव में स्थितियां सुखद नहीं रहेंगी यह तय है।

सुक्खु सरकार के पहले बजट पर लगी निगाहें गारंटीयों के लिये धन का जुगाड़ कैसे किया जायेगा

- क्या यह सरकार भी कर्ज लेकर काम चलायेगी
- क्या सेवाएं महंगी करके और कर लगाकर राहतें दी जायेंगी

शिमला/शैल। सुक्खु सरकार के पहले बजट पर पूरे प्रदेश की निगाहें लगी हुई हैं क्योंकि इस सरकार को विरासत में कोई सुखद वित्तीय स्थिति नहीं मिली है और चुनाव के दौरान जनता को दी दस गारंटीयों को पूरा करने की चुनौती है। कठिन वित्तीय स्थिति पर श्रीलंका जैसे हालात होने की आशंका तक सरकार व्यक्त कर चुकी है। पिछली सरकार के नाम कर्ज लेने वाली सरकार का तमगा लग चुका है। पिछली सरकार ने अन्तिम छः माह में जो संस्थान खोले थे उनसे प्रदेश पर पांच हजार करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ना था इसलिये वह बन्द कर दिये गये हैं। लेकिन जो गारंटीयां पूरी की जानी है उनमें 1,34,000 कर्मचारियों को ओल्ड पैन्शन का लाभ दिया जाना है और यह अन्तिम वेतन का 50% होती है। इसके अतिरिक्त 1,34,000 महिलाओं को 1500 रूपये प्रति माह दिये जाने हैं। इन्हीं दो मदों पर करीब 5000 करोड़ का वार्षिक खर्च होने का अनुमान है। इसी के साथ 300 यूनिट बिजली मुफ्त देनी है। इस सबको सामने रखते हुए यह देखना रोचक होगा कि इतने धन का प्रावधान यदि कर्ज लेकर किया जाता है तो पांच वर्षों में यह कर्ज ही 25000 करोड़ हो जायेगा। यदि कर लगाकर या सेवाएं महंगी करके प्रबन्ध किया जाता है तो पहले ही महंगाई और बेरोजगारी से त्राहि-त्राहि कर रही जनता पर और बोझ पड़ेगा। इसलिये यह सरकार और उसके सलाहकारों की परीक्षा होगी कि वह कैसे जनता पर कोई बोझ डाले बिना इस धन का प्रबन्ध करते हैं। क्योंकि विद्युत परियोजनाओं के लिये पानी पर जो सैस लगाने की योजना चर्चा में चल रही है उससे अन्तिम परिणाम में किसी को तो बिजली महंगी मिलेगी। जबकि इसी प्रदेश में सन 1990 में शान्ता कुमार की सरकार बनी थी तब बसपा परियोजना बिजली बोर्ड से लेकर जे.पी. उद्योग समूह को दी गयी थी। उस समय बिजली बोर्ड जो पैसा इस परियोजना पर करीब पन्द्रह सोलह करोड़ लगा चुका था उसे 16% ब्याज सहित बोर्ड को वापिस करने का अनुबंध हुआ था। शान्ता सरकार के बाद वीरभद्र और धूमल की सरकारें भी आकर चली गयी। लेकिन जे पी उद्योग यह पैसा वापिस नहीं कर पाया। तब यह तय हुआ कि जब बसपा में उत्पादन शुरू हो जायेगा तब जे.पी. से पैसा वापस लिया जायेगा। लेकिन जब उत्पादन शुरू हो गया और पैसा वापस करने की बात आयी तब सरकार ने यह फैसला दिया कि यदि अब यह पैसा वापस लिया जाता है तो इसका बोझ अप्रत्यक्ष में जे पी जनता पर डालेगा क्योंकि बिजली महंगी दरों पर देगा। इस तरह अन्त में करीब 92 करोड़ रूपया बट्टे खाते में डाल दिया गया। कैग ने सरकार के इस फैसले पर आपत्ति भी जताई है। लेकिन पैसा वापस नहीं मिला। ऐसे में यदि अब जनता पर परोक्ष/अपरोक्ष में कोई बोझ डाला जाता है तो उसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ेगा।